THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) to (d). Gross investment in Central public enterprises in Uttar Pradesh was Rs. 802.28 crores at the end of March, 1980. There cannot be any question of ignoring any particular district or districts as location of public sector units is governed by positive factors.

It will be explored if during VIth Plan period any public sector unit would be located in the Gonda district in U P.

Shortage of Coal for Cement Industries in Orissa

*424 SHRI A. C DAS Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether some Cement Industries have been affected severely due to shortage of coal,

(b) whether any such cement industry of Orissa has suffered a set-back for the above reasons, and

(c) if so, the steps taken by Government for the easy movement of coal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI CHARANJIT CHANANA): (a) Yes, Sir. Some of the cement factories have reported short supplies of cool.

(b) There are two cement factories in Orissa, namely Hira Cement Works, Bargarh and Orissa Cements Ltd., Rajgangpur. Even though shortage of Coal has been experienced, the capacity utilisation of these two factories in 1980 has been 101 and 102 percent respectively.

(c) The coal supplies to cement factories are reviewed regularly and steps taken to step up coal supplies to the cement industry.

बड़ौदा में एक नया कर्मचारी भविष्य निधि क्षेत्रीय कार्यालय का खोला जाना

425. श्री नृसिंह मकवाना: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बड़ौदा में बड़ौदा और पंच महल जिलों के लिए क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए गुजरात रीजनल कमेटी आफ वर्क्स प्रोविडेंट फण्ड की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिया गया निर्णय क्या है;

(ख) गुजरात के उन श्रमिकों की संख्या कितनी है जो भविष्य निधि के सदस्य हैं और उनमें से बड़ौदा और पंच महल जिलों के श्रमिकों की संख्या कितनी है; और

(ग) सूरत तथा राजकोट क्षेत्रीय कार्यालयों से सम्बद्ध सदस्य श्रमिकों की संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा): (क) बड़ौदा में उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोलने संबंधी सिफारिश अभी तक सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) विवरण मेज पर रख दिया गया है।

(ग) सूरत और राजकोट में कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है । तथापि, इन स्थानों में उप-क्षेत्रीय कार्यालय हैं । इन